

Note for Pad

Haryana Kaushal Rozgar Nigam Limited has been established with the mandate of providing contractual manpower in all Government Departments/ Boards/ Corporations etc. through online portal in a transparent manner based on notified criteria with the specific focus on the need to provide opportunities to Antodya families in the State. The Government had an apprehension that the contractual employees working through the contractors may not be getting adequate remuneration, facility of EPF, ESI etc. Therefore, Haryana Kaushal Rozgar Nigam Limited has been established by the Government with the aim of removing such irregularities and anomalies and thus earlier exploitation of manpower by Private contractor has been removed.

Haryana Kaushal Rozgar Nigam, in the process of providing contractual manpower focuses on:

- ❖ Uplifting youth from Antyodya families.
- ❖ Facilitating timely payment of remuneration and benefits to deployed manpower.
- ❖ Ensuring adherence to the reservation policy of the Government.

Deployments under HKRNL are being done as per Deployment of Contractual Persons Policy-2022 dated 30.6.2022, available on the Haryana Government's website. Deployments under HKRNL are being done through a tech enabled online portal in a completely transparent manner and without any human intervention. Remuneration of contractual employees is being disbursed directly in their bank accounts by the Nigam, which shows the robustness, strength and transparency of the system in-line with the Government's guidelines.

The Nigam has developed a portal having following salient features:

- i) All Government organizations can raise indent online, using their login/sub-login which will be approved by Finance department and forwarded to HKRNL for processing and deployment.

- ii) Shortlisting and Selection of candidates through a tech-enabled system-driven on the basis of a ranking matrix approved under the Deployment of Contractual Persons Policy, 2022 dated 30.6.2022 of Government of Haryana.
- iii) The existing contractual manpower working regularly as on 31.03.22 working in different Government organizations through the contractors are being ported to the Nigam portal as per the terms of the Deployment of Contractual Persons Policy, 2022 dated 30.6.2022 of Government of Haryana.
- iv) The payment of wages to the manpower is also done through the online portal
- v) All statutory compliances relating to labour welfare etc are also being taken care of.
- vi) 1,06,464 number existing contractual manpower in various Government organizations have been ported to the HKRNL Portal till date.

The selection / shortlisting of candidates by the Nigam is being done through the online portal, leaving no scope for any manual intervention, in a transparent way. Thus, educated youth of the state are provided with the opportunity of registration on the Haryana Kaushal Rozgar (HKRNL) Portal as detailed below.

- The educated youth having prior experience in any Government organizations/ Board/ Corporations etc (but not currently working) are given opportunity to register on the portal and their claimed experience is verified online from DDOs of respective organisations through the HKRNL Portal. The verified candidates from the pool of such registered candidates are considered for deployment on priority basis.
- The candidates which do not have any prior experience in any government entities are also given an opportunity to register themselves on the HKRNL portal through public advertisement. Such advertisements are published when sufficient number experienced candidates are not available in the registered pool of candidates of HKRNL portal against the demand of

various departments.

So far, Deployment Offer Letter (DOL) has been issued to 1,06,464/- existing contractual employees in various Government organizations, out of which 95,424/- contractual employees have joined on the Nigam portal and are working in various Government organizations. Further DOL has been issued to 6736 number fresh candidates for job activities like Yog Sahayak, Driver, Assistant Lineman, Art Education Assistant etc. out of which 4,380 number have joined services and are working in various Government Organizations.

▪

चर्चा हेतु टिप्पणी

हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की स्थापना सभी सरकारी विभागों/बोर्डों/निगमों आदि में अनुबंधित जनशक्ति को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी तरीके से अधिसूचित मानदंडों के आधार पर अंत्योदय परिवारों को अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देने के साथ की गई है। राज्य सरकार को आशंका थी कि ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को पर्याप्त पारिश्रमिक, ईपीएफ, ईएसआई आदि की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसलिए ऐसी अनियमितताओं और विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की स्थापना की गई है और इस प्रकार निजी ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा अनुबंधित श्रमशक्ति का शोषण समाप्त कर दिया गया है।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा अनुबंधित श्रमशक्ति प्रदान करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है:

- (क) अंत्योदय परिवारों के युवाओं का उत्थान।
- (ख) तैनात जनशक्ति को पारिश्रमिक और लाभों के समय पर भुगतान की सुविधा प्रदान करना।
- (ग) सरकार की आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित करना।

एच०के०आर०एन०एल के तहत नियुक्ति हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध Deployment of Contractual Persons Policy-2022 के अनुसार की जाती है। एच०के०आर०एन०एल के तहत नियुक्ति एक उच्च तकनीकी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से और किसी मानवीय हस्तक्षेप के बिना की जाती है। अनुबंधित कर्मचारियों के मेहनताने का वितरण सीधे उनके बैंक खातों में किया जाता है, जो सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रणाली की मजबूती और पारदर्शिता को दर्शाता है।

निगम ने निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं वाला एक पोर्टल विकसित किया है:

- i) सभी सरकारी संगठन अपने लॉगिन/उप-लॉगिन का उपयोग करके ऑनलाइन श्रमशक्ति की मांग कर सकते हैं, जिसे वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाता है और उनकी प्रोसेसिंग और नियुक्तियों के लिए एच०के०आर०एन०एल को भेजा जाता है।
- ii) हरियाणा सरकार की Deployment of Contractual Persons Policy-2022 के तहत रैंकिंग मैट्रिक्स के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग और चयन प्रक्रिया को उच्च तकनीक प्रणाली के माध्यम से लागू किया गया है।
- iii) हरियाणा सरकार की Deployment of Contractual Persons Policy-2022 की शर्तों के अनुसार, दिनांक 31.03.2022 को नियमित रूप से विभिन्न सरकारी संगठनों में ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत मौजूदा अनुबंधित श्रमशक्ति को निगम पोर्टल पर पोर्ट किया जाता है।

iv) श्रमशक्ति को मजदूरी का भुगतान भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।

v) श्रम कल्याण आदि से संबंधित सभी कानूनी नियमों का भी ध्यान रखा जाता है।

vi) विभिन्न सरकारी संगठनों में 1,06,464 से अधिक मौजूदा संविदात्मक जनशक्ति को अब तक एच०के०आर०एन०एल पोर्टल पर पोर्ट किया जा चुका है।

निगम द्वारा उम्मीदवारों का चयन/शॉर्टलिस्टिंग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से , पारदर्शी तरीके द्वारा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के किया जाता है। इस प्रकार ,राज्य के शिक्षित युवाओं को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पंजीकरण का अवसर प्रदान किया जाता है-

- किसी भी सरकारी संगठन/बोर्ड/निगम आदि में पूर्व अनुभव रखने वाले (लेकिन वर्तमान में काम नहीं कर रहे) शिक्षित युवाओं को पोर्टल पर पंजीकरण करने का अवसर दिया जाता है और उनके दावा किए गए अनुभव को पोर्टल के माध्यम से संबंधित संगठनों के डीडीओ से ऑनलाइन सत्यापित किया जाता है। ऐसे पंजीकृत उम्मीदवारों के पूल से सत्यापित उम्मीदवारों की प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की जाती है।
- जिन उम्मीदवारों को किसी भी सरकारी संस्था में कोई पूर्व अनुभव नहीं है, उन्हें भी सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से एच०के०आर०एन०एल पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करने का अवसर दिया जाता है। ऐसे विज्ञापन तब प्रकाशित किए जाते हैं जब विभिन्न विभागों की मांग के अनुरूप एच०के०आर०एन०एल पोर्टल के पंजीकृत उम्मीदवारों के पूल में पर्याप्त संख्या में अनुभवी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा विभिन्न सरकारी संगठनों में कार्यरत 1,06,464 मौजूदा अनुबंधित कर्मचारियों को डिप्लॉयमेंट ऑफर लैटर(डी०ओ०एल) जारी किया गया है, जिसमें से 95,424 अनुबंधित कर्मचारियों ने निगम के पोर्टल पर ज्वाइन कर लिया है और विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा 6736 नए उम्मीदवारों को जॉब एक्टिविटीज़ जैसे योग सहायक, चालक, सहायक लाइनमैन, कला शिक्षा सहायक इत्यादि में डी०ओ०एल जारी किया गया है, जिनमें से 4,380 उम्मीदवारों ने ज्वाइन कर लिया है और विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं।